

(11)
(22)

भाग-V

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी
जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

- 17- राज्य सरकार की सिफारिश:
(उपर्युक्त भाग- II या भाग- III या
भाग-IV में किसी अधिकारी या प्राधिकारी
द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर
विशिष्ट टिप्पणी की जाए)

हस्ताक्षर:

तिथि :

नाम और पदनाम

स्थान :

सरकारी मोहर

प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के मॉग का पूर्ण औचित्य

परियोजना का नाम :- जनपद नैनीताल में राज्य योजना के अन्तर्गत मंगोली-खमारी-
थापला-जलालगांव से देचौरी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

मंगोली से जलालगांव तक पूर्व में मोटर मार्ग निर्मित है। जिसमें वाहनों का आवागमन बना हुआ है। जलालगांव से देचौरी तक वर्तमान में कोई मार्ग आवागमन हेतु निर्मित नहीं है। स्थानीय ग्रामीणों को आवागमन की सुविधा प्रदान किये जाने हेतु जलालगांव से देचौरी तक 7.0 किमी० लम्बाई में मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु शासनादेश संख्या 883/111(2)/08-66 (एम०एल०ए०)/07 दिनांक 28.03.2008 द्वारा रू० 245.00 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुयी है। उक्त मार्ग के निर्माण के पश्चात् ग्रामीणों को 5.0 किमी० कम दूरी तय करनी पड़ेगी। उक्त मार्ग के निर्माण में 6.05 किमी० लम्बाई व 9.0 मी० चौड़ाई में आरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है। उक्त के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि मार्ग निर्माण हेतु उपलब्ध नहीं है। जैसा कि पृष्ठ सं० (12A) में संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में भी अंकित किया गया है। प्रस्तावित संमरखण में वृक्षों का पातन भी कम होगा तथा आरक्षित वन भूमि भी कम उपयोग होगी। इन्ही कारणों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त मार्ग के निर्माण हेतु 6.05 किमी० लम्बाई व 9.0 मी० चौड़ाई में वन भूमि हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव गठित किया गया है।

अपर सहायक अभियन्ता
प्रा०ख०, लो०नि०वि०,
नैनीताल

सहायक अभियन्ता
प्रा०ख०, लो०नि०वि०,
नैनीताल

अधिशाली अभियन्ता
प्रा०ख०, लो०नि०वि०,
नैनीताल

पत्र - 30

(for linear projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Nainital

No:-

Dated 20.11.14

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 5.445 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of P.D., P.W.D, Nainital for **Construction of Mangoli Khamari Thapla Jalalgaon Dechauri Motor Road** in Nainital district falls within jurisdiction of **Jalalgaon** village (s) in **Nainital** tehsil.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 5.445 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23.4 to _____ annexure _____
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

जिलाधिकारी
नैनीताल

जिला सहायक कल्याण अधिकारी
नैनीताल

जिला सहायक कल्याण अधिकारी
नैनीताल का प्रमाण, नैनीताल.

FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Nainital

No—

Dated-----

परियोजना का नाम :- जनपद नैनीताल में राज्य योजना के अन्तर्गत मंगोली-खमारी -थापला-जलालगौव से देचोरी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 5.445 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of P.D.P.W.D Nainital for Construction of Mangoli Khamari Thapla Jalalgaon Dechauri Motor Road for Road Work (purpose for diversion of forest land) in Nainital district falls within jurisdiction of Jalalgaon village (s) in Nainital tehsils.

It is further certified that:

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 5.445 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....
- the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the gram sabha of Nainital villages(s) is enclosed as annexure..... to annexure.....
- the discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Encl: As above.
देवीबाब

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

Handwritten signature and initials.

26

प्रारूप-30.1

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR

DISTRICT NAINITAL (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule
tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

meeting of the district level committee of Nainital district, constituted under FRA.
2006 was held under the chairmanship of Mr Deepak Rawat I.A.S district collector,,
Nainital on dated 20.11.14 at time 11.30 AM at Nainital in which application claiming
rights in Kotabag Tehsil area measuring 5.445 hect for the construction of Mangoli
hamari Thapla Jalalgaon to Dechauri in District Nainital under state sector forest
land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the
sub division level committee of Kotabag Tehsil sub division were discussed to consider
the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims
were found to have been made & hence District level committee recommend the above
case for diversion of land for the said purpose.

Place... Nainital

Dated... 20.11.14

District Collector-cum-Chairman

District Level Committee

Nainital

विभागाध्यक्ष कल्याण अधिकारी
नैनीताल

प्रमाणित कल्याण अधिकारी
नैनीताल, जम 5214 नैनीताल.

परियोजना का नाम- मंगोली-रकमदी-धापला-उल्लाखगोव दे चोरी भोरामफा नगर
कार्यालय उप जिलाधिकारी,

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति मंगोली-रकमदी-धापला-उल्लाखगोव दे चोरी के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के अन्तर्गत भोरामफा नगर

उपखण्ड मंगोली-रकमदी-धापला-उल्लाखगोव दे चोरी (4320 हे० आरक्षित वन भूमि.....हे०

सिविल एवं सोखम वनभूमि, वन पंचायत भूमि: 125 हे० अर्थात् कुल 544.5 हे० वन भूमि) का

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम

2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील मंगोली-रकमदी-धापला-उल्लाखगोव दे चोरी) की दिनांक 11/11/14 को

समन्वय बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री डॉ. राजीव चौरा उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

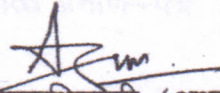
1. श्री राजीव चौरा उपजिलाधिकारी मंगोली-रकमदी-धापला-उल्लाखगोव दे चोरी अध्यक्ष
2. श्री म. व. चौरा उप प्रभागीय वनाधिकारी मंगोली-रकमदी-धापला-उल्लाखगोव दे चोरी सचिव
3. श्री मु. म. चौरा सहायक समाज कल्याण अधिकारी भोरामफा नगर सदस्य
4. श्री डॉ. राजीव चौरा बी.डी.सी क्षेत्र मंगोली-रकमदी-धापला-उल्लाखगोव दे चोरी सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई माननीय सदस्यों को संबोधित किया गया कि जनपद नैनीताल के अन्तर्गत मंगोली-रकमदी-धापला-उल्लाखगोव दे चोरी क्षेत्र में 544.5 हे० वन भूमि मंगोली-रकमदी-धापला-उल्लाखगोव दे चोरी क्षेत्र में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष आ रहा। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त वनभूमि तत्काल ही ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक स्थान हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

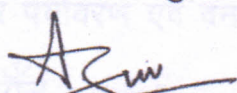
सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग नैनीताल द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है। अतः प्रकरण के उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड नैनीताल परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के अन्तर्गत मंगोली-रकमदी-धापला-उल्लाखगोव दे चोरी क्षेत्र में मंगोली-रकमदी-धापला-उल्लाखगोव दे चोरी क्षेत्र में

विद्योजना के निर्माण हेतु 5.145 हे० वनभूमि 14.145 हे० प्रयोक्ता एजेंसी
जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति
दिली गयी।


उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष,
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति,
तहसील-
जनपद- नैनीताल

जिलाधिकारी, नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष,
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति,
तहसील-
जनपद- नैनीताल।

प्रा.प. - 303

परियोजना का नाम :- मंगोली - खमारी - थापला - जलालगोव - डेचोरी मोर (14)

सर्व का नक्काशा

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - जलालगोव

हसील नैनीताल, जिला नैनीताल।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत मंगोली - खमारी - थापला - जलालगोव - डेचोरी निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु (4.32 हे० आरक्षित वन भूमि, सिविल हे०, वन पंचायत भूमि 1.125 हे०) अर्थात् कुल 5.445 हे० वन भूमि का विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत जलालगोव द्वारा दिनांक 19-10-2014 सम्मन ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा आवेदित वन भूमि सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई, यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों को स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु उक्त वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्तावित किया गया कि ग्राम जलालगोव के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 5.445 हे० को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

होती वाडेय
जलालगोव

यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि पर परियोजना के निर्माण हेतु आवश्यक विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र पर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

ह०/-



(गणेश सिंह महारा)
सदस्य जिला पंचायत
ज्योलीकोट (नैनीताल)

9118 2119

(गणेश सिंह महारा)
सदस्य जिला पंचायत
ज्योलीकोट (नैनीताल)


Cost Benefit Ratio Chart


Name of Project – Construction of Motor Road from Mangoli Khamari Thapla
Mangoli to Dechori.

Block :- Kotabagh

District :-Nainital

S.No.	Particulars	Amount (Lac Rs.)	Remark
1	Total cost (Investment incurred)		
(A)	Construction Cost of Project		Rs 24500000.00
(B)	N.P.V. Amount to be deposited @ 9.20 Lac/Hectare	Rs. 3065535.00	
(C)	Substitute/Alternation Planlation Cost to be Deposited :-	700000.00	
	Total	3765535.00	24500000.00
2	Benefits:-		
	Benefits from (Taking Age of Road As 50 Years)		
(A)	Economic Benefits- Taking Market Development	Rs.500.00	
(B)	Direct Employment of Labours-	Rs. 50.00	
(C)	Employment Generation Due to other activities	Rs. 70.00	
3	Therefore construction is Economically Viable and socially benfcial.		


 सहायक अभियन्ता
 प्रांतीय खण्ड, लो० नि० वि०
 नैनीताल


 अधिशासी अभियन्ता
 राष्ट्रीय खण्ड, लो० नि० वि०
 नैनीताल

32

FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Nainital

No—

Dated-----

परियोजना का नाम :- जनपद नैनीताल में राज्य योजना के अन्तर्गत मंगोली-खमारी -थापला-जलालगौव से देचोरी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 5.445 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of P.D.P.W.D Nainital for Construction of Mangoli Khamari Thapla Jalalgaon Dechauri Motor Road for Road Work (purpose for diversion of forest land) in Nainital district falls within jurisdiction of Jalalgaon village (s) in Nainital tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 5.445 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....
- (b) the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- (c) the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the gram sabha of Nainital villages(s) is enclosed as annexure..... to annexure.....
- (d) the discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (f) the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Signature
District Collector

(Full name and official seal of the District Collector)

Nainital